

मैन्यूफैक्चरिंग और निर्यात बढ़ाने के लिए नई स्कीम

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय दे रहा अंतिम रूप, इसके लिए **दर्जनभर सेक्टरों** का किया गया है चयन

जागरण ब्यूरो नई दिल्ली : मैन्यूफैक्चरिंग के साथ वस्तु निर्यात में बढ़ोतरी को लेकर वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय इन दिनों नई सरकार में अपने 100 दिनों के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक, मैन्यूफैक्चरिंग व निर्यात प्रोत्साहन के लिए दर्जन भर सेक्टर का चयन किया जा रहा है। इन सेक्टर में निर्यात बढ़ाने की बड़ी संभावना है, जिससे भारत दुनिया की सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बन सकेगा। सरकार वर्ष 2030 तक निर्यात को एक लाख करोड़ डालर तक ले जाना चाहती है और इन सेक्टर का इस लक्ष्य की प्राप्ति में अहम भूमिका हो सकती है।

इन सेक्टर में भारत को वैश्विक मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने के लिए उनकी यातायात, बिजली सप्लाई, लाजिस्टिक, डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी जरूरतों को पूरा करने की भी तैयारी की जाएगी। उनके लिए

- सरकार इन सेक्टरों के लिए यातायात, बिजली सप्लाई, लाजिस्टिक, डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी जरूरतों को करेगी पूरा
- उद्यमियों को नए बाजार से लेकर सस्ते दाम पर कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए सरकारी एजेंसियां करेंगी मदद



ऐसे नीतिगत फ्रेमवर्क तैयार किए जाएंगे जिससे उन्हें विभिन्न प्रकार की नियामक एजेंसियों के साथ नहीं उलझना पड़े और कम से कम प्रक्रियाओं का सामना करना पड़े। इनके टैक्स के प्रारूप को लेकर भी

कुछ बदलाव किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक दर्जनभर सेक्टर में मैन्यूफैक्चरिंग हब बनने के लिए उद्यमियों को इंसेंटिव देने से अधिक उनकी विभिन्न जरूरतों को पूरा करने पर जोर होगा। नए बाजार

फुटवियर को फोकस सेक्टर में किया गया है शामिल

ड्रोन और आटोमोबाइल सेक्टर को फोकस एरिया में इसलिए शामिल किया गया है, क्योंकि भारत में इन सेक्टर में अपने उत्पादन को काफी अधिक बढ़ाने की संभावना है। हाल ही में सरकार ने फुटवियर पर क्वालिटी कंट्रोल नियम लागू करने की घोषणा की है, जिससे फुटवियर इंडस्ट्री को बड़ा बूस्ट मिलेगा। इसलिए इसे फोकस सेक्टर में शामिल किया गया है।



मेडिकल डिवाइस में होंगे आत्मनिर्भर
भारत मोबाइल फोन निर्माण में बहुत हासिल करने के बाद अब सेमीकंडक्टर निर्माण की पूरी चेन को घरेलू स्तर पर विकसित करना चाहती है। इसलिए ईएसडीएम को फोकस सेक्टर में शामिल किया गया है। भारत जरूरत का 60 प्रतिशत से अधिक मेडिकल डिवाइस आयात करता है। इस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना है। केमिकल को भी फोकस एरिया में शामिल किया गया है।



से लेकर सस्ते दाम पर कच्चे माल की उपलब्धता में सरकारी एजेंसियां उनकी मदद कर सकती हैं। हो सकता है नई सरकार के गठन के 100 दिनों के भीतर इन सेक्टर के लिए इंसेंटिव की भी घोषणा हो।

ये सेक्टर किए गए हैं शामिल : आटो कंपोनेंट्स, आटोमोबाइल (इंजीन भी) कैपिटल गुड्स, केमिकल, इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्यूफैक्चरिंग (ईएसडीएम), मेडिकल डिवाइस, लेदर-फुटवियर।